सं. निदे.(एफ एंड वीपी)/43/सीएसी/एफएसएसएआई/09-Vol.- II

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांकः 22.02.2012

विषयः दिनांक 18 जनवरी, 2012 को 11 बजे शंगरी–ला'ज–इरोज होटल, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की छठी बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 18 जनवरी, 2012 को 11 बजे शंगरी–ला'ज–इरोज होटल, नई दिल्ली में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी.एन गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की छठीं बैठक का कार्यवृत अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

अतः अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को भेज दें, अन्यथा इस कार्यवृत्त को अंतिम माना जाएगा।

(डा. डी.एस. यादव)

उपनिदेशक (तक.)

फोन नं.: 011–23231681

ईमेलः dsyadav@fssai.gov.in

सेवा मेंः संलग्न सूची के अनुसार

सूची

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386004 ई–मेलः secy-agri@nic.in
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061252 ई–मेलः secyhfw@nic.in
3. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23388006 ई–मेलः secyahd@nic.in
4. सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386052 ई–मेलः secy-food@nic.in
5. सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23384716, ईमेलः secyca@fca.delhi.nic.in
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049, फैक्सः 26493012, ईमेलः secy.hub@nic.in
7. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061796 ईमेलः csoffice@nic.in
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23063045, ई–मेलः secretary-msme@nic.in
9. सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23389028, ई–मेलः secy-mopr@nic.in
10. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24361896 ई–मेलः envisect@nic.in
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23381495, ई–मेलः secy.wcd@nic.in
12. सचिव, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24362884 ई–मेलः mkbhan@dbt.nic.in
13. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटौली–मंगोट्रीयन, जम्मू–180007, जम्मू एवं कश्मीर। टेलीफैक्सः 0191– 2538527, 2538626, मोबाइलः09419180734, ई–मेलः controllerdrugsfood@yahoo.in
14. श्री अश्वनी कुमार राय (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्य प्रदेश और नियंत्रक औषधि (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार, ईदगाह हिल्स, भोपाल–462001, टेलीफैक्सः

0755–2665385, 2660690, मोबाइलः 9425302060 ई–मेलः fda_mp@hotmail.com, ashwini.rai@gmail.com

15. डा. बी.आर. मीना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजस्थान और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। टेली–फैक्सः 0141–2229858 मोबाइलः 09829164678, ई–मेलः directorph-rj@nic.in
16. डा. (श्रीमती) पी. सुचरित्रा मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त आंध्र प्रदेश और निदेशक, निवारक चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, नरयाणागुडा, हैदराबाद–500029, टेलीः 0140–27560191/27552203 फैक्सः 040–27567894 मोबाइलः +919849905228 ई–मेलः diripm@yahoo.co.in
17. श्री एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं 8, प्रथम तल, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010, गुजरात टेलीफोनः 079–23253417, 23253399, फैक्सः 079–2325333400, ई–मेलः hkoshia@yahoo.co.in, comfdca@gujarat.gov.in
18. श्री बी.एस. रामा प्रसाद (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्नाटक, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, कर्नाटक सरकार, आनंदा राव सर्किल, बैंगलौर–560009, टेलीः 080–22354085, 22874039, 22210248 फैक्सः 080–22201813, मोबाइलः 09448494094, ईमेलः comhfw@gmail.com
19. डा. एस. रविंद्रम (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त और रजिस्ट्रार, कॉ–ऑपरेटिव सोसाइटी, केरल, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त, थाइकुड, पीओ थिरूवनंथपुरम–695014, टेलीः 0471–22322833, 2322844 फैक्सः 0471–2322855, ई–मेलः foodsafetykerala@gmail.com
20. श्रीमती रजी पी. श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंजाब और एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन, एसआईएचएफडब्ल्यू कॉम्पलैक्स, फेज–6, समीपवर्ती सिविल अस्पताल, एसएएस नगर, मोहाली – 160056, पंजाब। टेलीः 0172–2266931, फैक्सः 0172–2266936, ईमेलः md_phsc@yahoo.in, hsg_68@yahoo.co.in
21. टी.एन. रमनाजीसन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडू और कार्यालयः आयुक्त, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, अरूमबक्कम, अन्ना नगर, चेन्नई–600106, टेलीः 044–26214718, 4335075, ईमेलः hfsec@tn.gov.in
22. श्री रूपेंद्र चौधरी (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम बंगाल और संयुक्त सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल, विंग "बी", जीएन–29, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकोता–7000091, टेलीफैक्सः 033–23574455, ईमेलः pd_wbsapcs@wbhealth.gov.in

23. श्री संजय कुमार सक्सेना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त दिल्ली, दिल्ली सरकार, ए–20, लारेंस रोड़, औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड़, दिल्ली–110035, टेलीः 011–27194858, फैक्सः 011–27153846, ई–मेलः dirpfa@nic.in
24. श्री कलिंग तयांग, (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), अरुणाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791111, टेली–फैक्सः 0360–2244513 फैक्सः 0360–2244183, ई–मेलः ktayeng@yahoo.com, ktayeng@rediffmail.com, arunachalfoodsafety@yahoo.co.in
25. श्री के.आर. मीना (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य और राजस्व, स्थानीय प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी–605001, टेली फैक्सः 0413–2334144, ई–मेलःsecylad@pon.nic.in, glu3959@yahoo.co.in
26. श्री महेश जगाडे (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त महाराष्ट्र और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र, एस.नं. 341, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलैक्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई–400051, टेलीः 022–26592207, 26590548, फैक्सः 022–26591959, मोबाइलः 09921007558, ईमेलः zmahesh@hotmail.com
27. श्री बी. विजयन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा और प्रधान सचिव एवं सचिव (स्वास्थ्य), सचिव कार्यालय(स्वास्थ्य), पोरवोरीम, गोवा–403521 टेलीः 0832-2419440, 2224639, फैक्सः 0832-2419687, ईमेलः b.vijayan@nic.in
28. श्री के. सुब्राह्मनियम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त छत्तीसगढ़ और नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, कालीबाड़ी, निकट महिला पुलिस स्टेशन, रायपुर–492001, टेलीः 0771-4080322 फैक्सः 0771-2221322, ईमेलः maniiyer1958@yahoo.co.in
29. श्री मनोज कुमार साहू (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन एवं दीव और कलक्टर, ओआईडीसी कैम्पस, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, सचिवालय फोर्ट क्षेत्र के निकट, मोती दमन–396220 टेलीः 0260-2230470, 2230689 फैक्सः 0260-2230570, ईमेलः collectordaman@gmail.com
30. श्री डी.के. तिवारी (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, चौथा तल, चंडीगढ़ यूटी सचिवालय, डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017, टेलीफैक्सः 0172-2740045, ईमेलः gulshangirdhar@yahoo.com, birsat80@yahoo.co.in
31. श्री सी.आर. राणा (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा और मिशन निदेशक एनआरएचएम, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, प्रयत्न भवन, बेज़ 55–58, सेक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा, टेलीः 0172- 2573922 फैक्सः 0172- 2580466, ईमेलः md-hrnrhm@nic.in

32. एस. रामास्वामी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय, देहरादून–248001, उत्तराखंड। फोनः 0135-2711718, 2712061 फैक्सः 0135-2712113 ईमेलः healthsecyuk@gmail.com
33. श्रीमती अर्चना अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त उ.प्र., सचिव और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, नवीन भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001, टेली–फैक्सः 0522-2237617, ईमेलः commissionerfda.up@gmail.com, fdaupgov@gmail.com
34. डा. श्यामाघन बिसवास, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा ओडिसा और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), विभाग प्रमुख भवन, भुवनेश्वर–751001, ओडिसा, टेलीः 0674-2396977 फैक्सः 0674-2390674 ईमेलः dph.orissa@gmail.com
35. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्टब्लेयर–744102, टेलीः 03192-233331, फैक्सः03192-232910, ईमेलः drsk_paul@yahoo.co.in
36. डा. पी. हजेला (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा असम और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहटी–781006, टेली–फैक्सः 0361-2237366, 2260900, ईमेलः prateek.hajela@gmail.com
37. श्री के. मोसिस चले, खाद्य सुरक्षा आयुक्त मणिपुर और आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मणिपुर सरकार, कमरा नं. 233, पुराना सचिवालय, इंफाल, मणिपुर–795001, फोनः 0385-2450682, 2450513, फैक्सः 0385- 2456395, ईमेलः mchalai@yahoo.co.in
38. श्री एस. के. राय (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, प्रधान सचिव त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय कॉम्प्लैक्स, खेजूर बगान, त्रिपुरा सरकार, अगरतला–799006, त्रिपुरा। टेलीः 0381-2415058, फैक्सः 0381-2410145, ईमेलः dfwpm_agt@yahoo.co.in, sudipkin@yahoo.com
39. श्री आर. एफ. लोठा, अतिरिक्त आयुक्त एफडीए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, कोहिमा–797001, नागालैण्ड, फोनः 0370-2270457, फैक्सः 0370-2270062, ईमेलः holin_z@yahoo.co.in
40. श्री डी. पी. वहलांग (आईएएस), आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), कमरा नं. 315, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय–793001, टेली–फैक्सः 0364-2226978, ईमेलः dwahlang@yahoo.com, sangma.dcfs@gmail.com
41. डा. के. भंडारी, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण) विभाग, सिक्किम सरकार, तशिलंग, गंगटोक–737102, फोनः 03592-202633, फैक्सः 03592-2204481, ईमेलःhealthsecyskm@yahoo.com

42. श्री एम. जोहमिंगथांगी (आईएएस), सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मिजोरम सरकार, सचिवालय, न्यू केपिटल कॉम्पलैक्स, एजावल–796001, मिजोरम, फोनः 0389- 2328895, फैक्सः 0389-2320162, ईमेलः secyhealthmiz@gmail.com, mspc.aizawl@gmail.com
43. श्री के. विद्यासागर (आईएएस), मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरांडा, रांची–834002, टेलीः 0651-2491033, फैक्सः 0651-2490314, ईमेलः kasi_vidyasagar@yahoo.co.in, kavisahealth@gmail.com
44. श्री संजय कुमार (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, विकास भवन, नया सचिवालय भवन, पटना–800001, टेलीः 0612-2215809, 2281232, फैक्सः 0612-2224608, ईमेलः ed_shsb@yahoo.co.in, health-bih@nic.in
45. श्री अली रज़ा रिज़वी, आईएएस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, एच.पी. सचिवालय, शिमला–171002 टेली–फैक्सः 0177-2621904, ईमेलः healthsecy-hp@nic.in, dhsr.hp@gmail.com
46. श्री संजय गोयल (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर, कलेक्टोरेट, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली–396230 फोनः 0260-2642721, 2644203, फैक्सः 0260-2642787, ईमेलः collector-dnh@nic.in.
47. डा. एन. वसंथा कुमार, कलेक्टर एवं विकास आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारती–682555, एचपीओ कोची, टेलीः 04896-262256, फैक्सः 04896-263180, ईमेलः lk-coll@nic.in
48. श्री समीर बर्दे, सहायक महासचिव, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फिक्की का फूड विंग) / रिटेल, फोन नंः 23311920, 23738162, 23738760-70 (विस्तार) 310, ईमेलः sameer@ficci.com
49. श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया फूड प्रोडक्टस, 48/ए, पार्वती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अदीनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे–सतारा रोड़, पुणे–411009, टेलीः 09922990064, ईमेल:admin@chordia.com
50. डा. जे टोनपांयोगंडगं वेलिंग, गांव–सनग्रतसु, जिलाः मोकोकचंग, नागालैंड।
51. श्री अरूण बालामट्टी, 815, 7वां क्रास, बनशंकरी, तीसरा फेज, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बैंगलोर–560085
52. श्री आर. देसीकन, फांउडर ट्रस्टी, कंसर्ट एडं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3/242 राजेंद्र गार्डन, वेटुवनकेनी, चेन्नई–600041, टेली/फैक्सः (044)24494576, (044)24494578 ईमेलः nirdesi@gmail.com, cai.india1@gmail.com

53. श्रीमती केया घोष, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कोलकोता रिसोर्स सेंटर, 3 सुरेन टैगोर रोड़, दूसरा तल, कोलकोता–700019, प. बंगाल, टेलीफैक्सः 033-24604987, फोन 033-24604985, ईमेलः calcutta@cuts.org
54. डा. एस.पी. वेसीरेड्डी, अध्यक्ष एंव प्रंबध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज–II, चेरलापल्ली, हैदराबाद–500051, आंध्र प्रदेश, टेलीः 040-27264141, 040-27264444, फैक्सः 040-27263657, ईमेलः mdo@vimta.com
55. प्रोफेसर गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैगंलोर (आईआईएमबी), बैनरघटा रोड़, बैंगलोर–560076, फोनः 080-26993194, ईमेलः gopaln@iimb.ernet.in

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष के पीपीएस, एफएसएसएआई
2. सीईओ के पीएस, एफएसएसएआई
3. निदेशक (प्रव.) के पीएस
4. सारे संबधित अधिकारी, एफएसएसएआई

दिनांक 18 जनवरी 2012 को शांगरी–ला'ज–इरोज होटल, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति(सीएसी) की छठी बैठक के कार्यवृत्त।

श्री वी.एन. गौड़, सीईओ, एफएसएसएआई और अध्यक्ष, सीएसी, केंद्रीय सलाहकार समिति ने छठी बैठक में सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकरण के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की शुरुआत के बाद यह दूसरी बैठक है, राज्यों द्वारा एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के संचालन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सीएसी राज्यों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच है क्योंकि इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है और राज्यों द्वारा अब तक उठाए गए सभी मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा एक विशाल क्षेत्र है हर व्यक्ति एक हितधारक है, इसलिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, और यह लड़ाई एक सतत लड़ी जाने वाली लड़ाई है। अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ अतिव्यापी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां जैसे कि कीटनाशक अवशेषों आदि मौजूद हैं, जो किसानों के खेतों से आती हैं, प्रसंस्करण के बाद के चरणों में इन्हें हटाना मुश्किल है, हालांकि, किसानों और मछुआरों को एफएसएस अधिनियम के दायरे से मुक्त रखा गया है। इसलिए, एफएसएसएआई कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श से अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में वैज्ञानिक पैनलों और समिति ने करीब 25 बार मुलाकात की और उनके द्वारा कई कार्यसूची मदों पर विचार किया गया या विचाराधीन है। टीएफए के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया में हैं और न्यूट्रकक्यूटिकल्स, लेबलिंग और दावे, पूरक खाद्य और आयातित खाद्य सुरक्षा पर मसौदा नियमन और आयातित खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं और खाद्य प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक देश में खाद्य व्यापार संचालको (एफबीओज) की संख्या का कोई प्रामाणिक डेटा न होने का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि लाइसेंस और पंजीकरण के क्षेत्रों पर जोर दिया और कहा कि इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार हमें प्रत्येक खाद्य व्यापार संचालक को रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, लाइसेंस के लिए पूर्व निरीक्षण को एफएसएस अधिनियम, 2006 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित लाइसेंस के हस्तांतरण के कानून/आदेश या विशिष्ट समय अवधि के लिए मौजूदा लाइसेंस के नवीकरण के साथ किया जाना चाहिए। उनकी राय थी कि राज्यों को बुनियादी ढांचे और क्षमता का विकास करना चाहिए ताकि समय के साथ वे एफएसएसएआई

/केंद्रीय लाइसेंसिंग की ओर से केंद्रीय लाइसेंस जारी करना शुरू कर सकें।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने परीक्षण और पूरे भारत में खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए कई प्रयोगशालाओं को अधिसूचित और खाद्य उत्पादों के विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए लागत को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/राज्य/नगर निगमों के विकास और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एफएसएसएआई जल्द ही विभिन्न एजेंसियों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा।

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पास हितधारकों से जानकारी/शिकायत प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी होना चाहिए और केंद्रीय प्राधिकरण को अधिकारी के संपर्क नंबर की जानकारी भेजी जानी चाहिए ताकि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी शिकायत को संबंधित आधिकारी को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपनी जानकारी को अद्यतित करना चाहिए और नियमित रूप से केंद्रीय प्राधिकरण को मासिक रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए।

<u>कार्यसूची मद सं. 1:</u> 27 सितम्बर 2011 को आयोजित सीएसी की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति ने बिना किसी टिप्पणी के, 27 सितंबर, 2011 को आयोजित सीएसी की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी

<u>कार्यसूची मद सं. 2:</u> एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति।

अध्यक्ष के कहा कि कार्यसूची में कुछ मदों की अतिव्याप्ति के कारण, कार्यसूची मद सं. 3, 5 और 6 पर भी ऊपर की कार्यसूची मदों के साथ विचार–विमर्श किया जा सकता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश ने एफएसएस अधिनियम, 2006 को लागू करने की प्रक्रिया में उन के द्वारा पहले की गई या की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

1) पश्चिम बंगाल:

- खाद्य सुरक्षा के लिए कोई अलग विभाग नहीं है, खाद्य प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग के साथ जोड़ दिया गया है। वर्तमान में, वहाँ स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा साझा वेबसाइट के लिए है लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए अलग से हाइपरलिंक किया / बनाया गया है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त और 19 अंशकालीन नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। पीएफए के सभी 66 खाद्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों को एफएसओ में परिवर्तित कर दिया गया है और 20 पूर्ण कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है और 46 पद रिक्त हैं। इस रिक्ति को भरने के लिए मानव संसाधन विकास बोर्ड से अनुरोध किया गया है

जिसमें दो महीने का समय लग जाएगा।

- 6 प्रयोगशालाओं में से 5 एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। 6 खाद्य विश्लेषकों को भी अधिसूचित किया गया है
- 14 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- कोलकाता नगर निगम द्वारा लाइसेंस देने का काम एक आम विंडो से किया जा रहा है
- ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है
- 'स्वास्थ्य विभाग' के तहत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक हेल्पलाइन कार्य कर रही है। वे खाद्य सुरक्षा को इसी हेल्पलाइन से एकीकृत करने की योजना बना रहे हैं
- उनकी प्राथमिकता मौजूदा पीएफए लाइसेंसों को एफएसएसए लाइसेंस में परिवर्तित करना है
- अभी उनके बजट आवंटन शीर्ष को पीएफए से एफएसएसए में परिवर्तित नहीं किया गया है।

2) गुजरातः

- राज्य में खाद्य सुरक्षा को खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन आयुक्त से जोड़ा गया है, 30 पूर्ण कालिक नामित अधिकारी, 162 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (पूर्ण कालिक) और 10 खाद्य विश्लेषकों और 4 एओएस को अधिसूचित किया गया है
- यानी 5 अगस्त, 2011 से एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यकारी होने के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 25 नए पदों और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 19 पदों को मंजूरी दी गई है।
- राज्य में 6 प्रयोगशालाएं हैः तीन सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से दो एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं, और 3 निगम प्रयोगशालाएं हैं, जिनके उन्नयन के लिए अनुदान दिया गया है,
- सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण को मंजूरी दी है, जो एक महीने के भीतर कार्यकारी हो जाएगा। पीठासीन अधिकारियों को अनुमोदित किया गया है
- 2 मोबाइल वैन खरीदी गई हैं, एक अधिनियम के निष्पादन के लिए है और अन्य प्रयोगशाला एवं निगरानी के लिए है
- 13 जनवरी 2012 को ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई थी। लाइसेंस के लिए 125 आवेदन पत्र प्राप्त किये गए हैं और 45 पंजीकरण किए गए हैं।
- शिकायत /असंतोष से निपटने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन (1800 233 5500) और शिकायत प्रकोष्ठ आरंभ किया गया है
- राज्य ने दिसम्बर 2011 तक 30 जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
- एफडीए के 2 संयुक्त आयुक्तों को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इस संबंध में, अध्यक्ष ने सूचित किया कि सभी नियुक्तियां/अधिसूचनाएंएफएसएस अधिनियम,

2006 और एफएसएस नियम, 2011 के तहत निर्धारित योग्यता और रैंक के साथ अनुरूपता में होनी चाहिए।

3) उड़ीसा:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है
- पीएफए के तहत खाद्य निरीक्षकों को एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- प्रत्येक जिले के लोक स्वास्थ्य अधिकारी को नामित अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- न्यायनिर्णयन अधिकारी को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है
- हेल्पलाइन और वेबसाइट के निर्माण के लिए कोष की आवश्यकता के बारे में फाइल वित्तपोषण के लिए विभाग को भेज दी गई है
- 4 और 5 फरवरी, 2012 के दौरान भुवनेश्वर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है
- आज तक अधिकारियों का कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है

4) दिल्ली:

- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग स्थापित किया गया है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों, 32 पूर्णकालिक
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नौ न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। एलएचए को नामित अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है
- राज्य स्तर पर हेल्पलाइन शुरू की गई है
- राज्य में एक प्रयोगशाला है और इसे एनएबीएल प्रमाणन प्राप्त है। पूरे राज्य के लिए दो खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया गया है
- तीन नामित अधिकारियों और पाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एफएसएसएआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- न्यायनिर्णयन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है
- राज्य द्वारा तीन उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
- विभाग ने विश्लेषण के लिए 256 नमूने एकत्र किए इनमें से 28 नमूने असुरक्षित पाए गए और 32 नमूनों को गलत ब्रॉड वाला पाया गया
- अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी निगरानी के प्रयोजन के लिए नमूनों को प्रयोगशाला में भेजेगा तो यह कदाचार को बढ़ावा दे सकता है अभियोजन पक्ष के बारे में निर्णय

में पक्षपात हो सकता है, इसलिए इस अभ्यास बंद कर दिया जाना चाहिए।

5) पंजाबः

- खाद्य सुरक्षा के लिए अलग विभाग की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। मौजूदा खाद्य निरीक्षकों को एफएसओ के रूप में पुनर्नामित किया गया है
- हर जिले में एडीएम को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- राज्य खाद्य सुरक्षा पर हेल्पलाइन बनाने की प्रक्रिया में है
- लाइसेंस देने की मैनुअल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने में समय लगेगा
- राज्य में एक खाद्य प्रयोगशाला है और यह एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत है
- राज्य में दो भोजन विश्लेषक अधिसूचित किए गए हैं

6) उत्तर प्रदेशः

- खाद्य सुरक्षा का एक अलग विभाग स्थापित किया गया है
- राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 70 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों, 290 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 72 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- राज्य में 6 प्रयोगशालाएं है लेकिन इनमें से कोई भी एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है।
- राज्य में एक खाद्य विश्लेषक है, लेकिन अधिक की आवश्यकता है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सूचित किया कि राज्य में 5000 नमूने एकत्र किए गए हैं और अब तक विफल नमूनों का प्रतिशत 18% से बढ़कर 40% हो गया है।
- अभी तक पंजीकरण अधिकारियो की अधिसूचना नहीं दी गई है
- हेल्पलाइन ने काम शुरू कर दिया है और यह प्राधिकरण के वेबसाइट से जुड़ी हुई है। एक उप निदेशक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर तैयार की जाएगी
- राज्य अपना निजी ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में सीईओ ने कहा कि विकसित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का प्रारूप एफएसएसएआई सॉफ्टवेयर के समान रहना चाहिए ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे

7) महाराष्ट्रः

- एफडीए का अलग विभाग स्थापित किया गया है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित कर दिया गया है
- राज्य में 30 पूर्ण कालिक नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया है और सरकार द्वारा नामित अधिकारियों के 32 और पदों का मंजूरी दी गई है।
- 265 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है और नगर निगमों के साथ काम कर रहे 58 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का विलय किया गया है।
- राज्य में सात प्रयोगशालाएं चल रही हैं, जिनमें से केवल एक प्रयोगशाला एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। पूरे राज्य में 8 नई प्रयोगशालाएं बनाने की कोशिश की जा रही है।
- हर जिले में एक मोबाइल प्रयोगशाला वैन के लिए योजना बनाई जा रही है।
- राज्य की हेल्पलाइन स्थापित है। इसके अलावा, एसएमएस आधारित सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया चल रही है
- विभाग के 7 संयुक्त आयुक्तों को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- लाइसेंस के लिए प्राप्त कुल 79,733 आवेदन पत्रों में से, राज्य ने 6036 लाइसेंस जारी किए हैं। पंजीकरण के लिए 25,159 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनसें से 18,636 पंजीकरण किए गए हैं।

8) मध्य प्रदेशः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 50 अंशकालिक नामित अधिकारी, 175 पूर्ण कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 50 एओएस को अधिसूचित किया गया है।
- राज्य में केवल एक प्रयोगशाला है और वह नमूनों के विश्लेषण के लिए अनाधिकारिक रूप से औषध प्रयोगशाला का समर्थन ले रही है क्योंकि उपकरणों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है।
- न्यायनिर्णयन अधिकारी ने घी में मिलावट करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
- ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली कार्यक्षम होने के लिए तैयार है
- पीएफए के तहत प्रयोगशालाओं के लिए अंतराल विश्लेषण किया गया है और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए सरकार को प्रस्ताव ऊपर भेजा गया है
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा रही है
- हेल्पलाइन ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। अधिनियम के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में आयोजित किया जाना है। इस पर सीईओ ने बताया कि प्रशिक्षण के दो

चरण हैं: प्रारंभिक संक्रमण प्रशिक्षण चरण को राज्य के द्वारा अपने दम पर नियंत्रित किया जाना है, जब तक एफएसएसएआई राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न कर ले।

9) चंडीगढ:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एक अंशकालिक नामित अधिकारी, 3 पूर्ण कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एक न्यायनिर्णयन अधिकारी को अधिसूचित कर दिया गया है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रवर्तन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है
- नामित अधिकारी और एओ का प्रशिक्षण अभी भी लंबित है
- राज्य ने 2 खाद्य विश्लेषकों के साथ दो प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल निर्माण की प्रक्रिया के अधीन है
- विशेष न्यायालयों के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचित किया गया है, और सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत है
- राज्य से आधिकारी ने कहा कि नामित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अनुस्मारक एफएसएसएआई को भेज दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

10) कर्नाटक:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 31 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों, 104 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 30 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग अभी तक स्थापित नहीं किया गया है
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की अधिसूचना प्रक्रिया के तहत है
- राज्य में 5 प्रयोगशालाएं हैं और कोई भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है
- राज्य में आठ खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया गया है
- लाइसेंस के 20 आवेदनों में से 7 लाइसेंस जारी किए गए हैं और राज्य में किए गए पंजीकरण की संख्या 108 है
- सभी अधिकारियों के लिए प्रवर्तन प्रशिक्षण पूरा हो गया है
- पदों का निर्माण और भर्ती के नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं
- राज्य ने अभी तक हेल्पलाइन शुरू नहीं की है

11) मेघालय:

- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग अभी तक बनाया जा रहा है

- राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों, 5 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 7 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- राज्य ने पीठासीन अधिकारी को अधिसूचित किया है
- लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है
- अब तक एफएसएस अधिनियम, नियम एवं विनियमों के तहत 25 लाइसेंस जारी किए गए हैं
- राज्य की प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, बुनियादी ढांचे की कमी है लेकिन अंतराल विश्लेषण किया गया है
- राज्य का अपना कोई खाद्य विश्लेषक नहीं है और असम सरकार के भोजन विश्लेषक की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है
- राज्य स्तर हेल्पलाइन और वेबसाइट अभी तक नहीं बनाई गई है
- लाइसेंस और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने और सॉफ्टवेयर अनुरूपण प्रदान करने के हित की पुष्टि करते हुए और सर्वर के रखरखाव और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एफएसएसएआई को पत्र लिखा गया है
- अब तक हितधारकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है

12) अरुणाचल प्रदेश:

- अभी तक खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग नहीं बनाया गया
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है
- 16 नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। जिनमें से एक अंशकालिक और तीन पूर्णकालिक हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी अधिसूचित कर दिया गया है
- एफएसएस नियमों और विनियमों के तहत खाद्य व्यापार के पंजीकरण और लाइसेंस के लिए प्रणाली शुरू कर दी गई है
- राज्य में कोई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, असम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं नामित अधिकारियों का प्रशिक्षण हो चुका है
- हेल्पलाइन आरंभ नहीं की गई है

13) मिजोरम:

- खाद्य सुरक्षा के अलग विभाग की स्थापना चल रही है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया गया है और दो पूर्णकालिक और 12 अंशकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है
- नामित अधिकारियों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है (3 नामित अधिकारी प्रस्तावित)

- राज्य में कोई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है
- 2 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- हेल्पलाइन अभी तक शुरू नहीं हुई है
- राज्य में 18 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं

14) उत्तराखंडः

- स्वास्थ्य सचिव को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है
- मुख्य खाद्य निरीक्षकों को नामित अधिकारियों (12 पूर्णकालिक) के रूप में अधिसूचित किया गया है, 34 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 13 एओएस को अधिसूचित किया गया है
- लाइसेंस और पंजीकरण के लिए मैनुअल प्रणाली कार्यात्मक है
- राज्य की एकमात्र प्रयोगशाला रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। क्यूसीआई ने एनएबीएल मान्यता के संबंध में प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया है। एक खाद्य विश्लेषक अधिसूचित कर दिया गया है
- हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभी तक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।
- लाइसेंस/पंजीकरण के संबंध में व्यापार मंडल और व्यापार सभा के साथ विचार–विमर्श सत्र आयोजित किया गया है
- अभी तक हेल्पलाइन नहीं बनाई गई है। अभी तक शिकायतों के निपटान के लिए नोडल अधिकारी नामित नहीं किया है

15) बिहारः

- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग अभी तक नहीं बनाया गया
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 पूर्णकालिक नामित अधिकारियों, 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (पूर्णकालिक) और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया है
- सभी नामित अधिकारी अधिनियम के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- राज्य में एक प्रयोगशाला है जो एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है
- मैनुअल लाइसेंस/पंजीकरण पहले ही शुरू कर दिया गया है। 679 पंजीकरण और 476 लाइसेंस जारी किए गए
- न्यायनिर्णयन अधिकारी/अपीलीय न्यायाधिकरण/विशेष अदालत की नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और प्रक्रिया के तहत है
- वेबसाइट के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है

- खाद्य सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है
- जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है
- कुल 750 नमूने (एफएसएसएआई) और सर्वेक्षण के 18 नमूने एकत्र किए गए हैं और प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा गया है

16) छत्तीसगढः

- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग बनाया नहीं किया गया है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं 18 अंशकालिक नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। 27 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है जिनमें से 14 अंशकालिक के रूप में काम कर रहे हैं।
- सभी नामित अधिकारी अपने जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।
- राज्य में केवल एक प्रयोगशाला मौजूद है जो एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है
- 2 खाद्य विश्लेषकों अधिसूचित किया गया है
- उपकरणों की ऑनलाइन खरीद का कार्य प्रगति पर है
- खाद्य व्यापार के पंजीकरण और लाइसेंस के लिए प्रणालियां विकास की प्रक्रिया में हैं।
- सरकार की मदद से संस्थानों के खाद्य नमूनों के सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण पर प्रयोगशाला कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- सभी 18 जिलों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों (एडीएमएस) को न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है
- प्रत्येक नामित अधिकारी के कार्यालय में हेल्पलाइन सुविधा विकसित की जाएगी जो एफएसएसएआई हेल्पलाइन और वेबसाइट के साथ एकीकृत होगी
- अक्टूबर, 2011 के महीने में रायपुर में एफएसएस अधिनियम/नियमों/विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था

17) नागालैंडः

- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है
- 11 अंशकालिक नामित अधिकारियों, 8 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एक खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया है
- खाद्य व्यापार संचालकों के लाइसेंस और पंजीकरण के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया गया है
- राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है जो एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, लेकिन नामित अधिकारियों

के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अभी बाकी है

- हेल्पलाइन अभी तक शुरू नहीं की गई है

18) तमिलनाडुः

- 5 जनवरी, 2012 से खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने प्रभार ले लिया है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कुल 584 पदों का सृजन किया गया है और पूर्णकालिक आधार पर 32 नामित अधिकारियों को तथा 32 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है
- राज्य में 6 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और 6 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित कर दिया गया है
- प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं
- मोबाइल प्रयोगशाला की कोई भी सुविधा नहीं है
- फरवरी 2012 के पहले सप्ताह में नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के लिए एफएसएसएआई में भेजा जाएगा
- खाद्य व्यापार के पंजीकरण और लाइसेंस के लिए प्रणाली प्रक्रिया के अधीन है
- राज्य ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने के लिए उत्सुक है
- हेल्पलाइन अभी तक शुरू नहीं की गई है
- राज्य में विशेष रूप से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में एनआरएचएम की एक मजबूत संरचना है,

19) हिमाचल प्रदेशः

- राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा और नियमन का अलग निदेशालय बनाया गया है,
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है और वे अपने स्थान पर हैं
- अगस्त 2012 से पहले पूर्णकालिक नामित अधिकारियों तैनात करने की योजना है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के दो दौर उपलब्ध कराए गए हैं
- राज्य प्रयोगशालाओं के लिए अंतराल विश्लेषण किया गया है और वे एनएबीएल मानकों के लिए उन्नयन की प्रक्रिया में हैं
- एनआरएचएम मजबूत करने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है
- ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली को सक्रिय करने के लिए एफएसएसएआई को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है
- आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ईओआई जारी किए गए हैं
- हेल्पलाइन सुविधा अभी तक शुरू नहीं की गई है

20) पांडिचेरी:

- केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है
- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग बनाया गया है
- 21 नए पदों का सृजन करने के लिए कार्य योजना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है
- नामित अधिकारी, 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एक खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया है
- केन्द्र शासित प्रदेश में एक प्रयोगशाला है और अंतराल विश्लेषण किया गया है और एनएबीएल मान्यता का कार्य प्रगति पर है
- वरिष्ठ लोक विश्लेषक को खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किया गया है
- मोबाइल प्रयोगशाला की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है
- पंजीकरण के लिए अब तक 300 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं इनमें से खाद्य व्यापार संचालकों को 227 पंजीकरण जारी किए गए हैं
- लाइसेंस देने की प्रक्रिया प्रगति पर है
- हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसे लागू करने के लिए धन की आवश्यकता है
- 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 1 नामित अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं
- भोजन और पानी के 600 नमूनों का विश्लेषण किया गया है

21) गोवा:

- राज्य में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को संभालने के लिए एकल एजेंसी है
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, 2 वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 2 नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- राज्य में एक प्रयोगशाला है
- 2 खाद्य विश्लेषकों और एक न्यायनिर्णयन अधिकारी को अधिसूचित किया गया है
- मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है
- लाइसेंस के लिए 1500 आवेदन प्राप्त किए गए हैं और खाद्य व्यापार संचालकों को 100 लाइसेंस जारी किए गए हैं
- स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय, पर्चे और पुस्तिकाओं के साथ जागरूकता अभियान पूरे जोर पर हैं
- एनआईएसजी द्वारा भुगतान के प्रवेश द्वार सहित ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण के लिए

प्रायोग प्रस्तावित है

- अंतराल विश्लेषण के अनुसार प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है। सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के परीक्षण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता आवश्यक है
- 95 लाख रुपए की लागत से प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
- स्वतंत्र वेबसाइट है
- नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है
- हेल्पलाइन सक्षम की गई है
- पंजीकरण के लिए 4500 आवेदन प्राप्त किए गए है और 1000 पंजीकरण जारी किए गए हैं

22) मणिपुरः

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है
- उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है
- 9 नामित अधिकारियों, 9 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 3 न्यायनिर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- म्यांमार सीमा क्षेत्र के पास एक प्रयोगशाला है और एक खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया गया है
- एक और प्रयोगशाला के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है
- प्रयोगशाला के लिए क्यूसीआई द्वारा अंतराल विश्लेषण आयोजित किया गया है
- मौजूदा प्रयोगशाला को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उन्नत किया जा रहा है
- अतिरिक्त 30 पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही हैं
- मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है
- लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत है
- हेल्पलाइन और वेबसाइट की प्रक्रिया भी चल रही है
- नोडल कार्यालय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है
- सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है

23) जम्मू एवं कश्मीरः

- एफडीए और खाद्य सुरक्षा के लिए साझा विभाग स्थापित किया गया है
- जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा के उपायुक्त अधिसूचित किए गए हैं
- 22 जिलों के लिए 25 नामित अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं जिनमें से 23 पूर्णकालिक और

दो अंशकालिक आधार पर हैं

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किया गया है
- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- खाद्य सुरक्षा ट्रिब्यूनल का निर्माण सरकार के विचाराधीन हैं
- जम्मू में एफडीए प्रधान कार्यालय में हेल्पलाइन सक्षम की गई है, लेकिन यह निःशुल्क नहीं है
- वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया के तहत है
- राज्य में दो अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन ये एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
- खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया गया है
- नामित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अभी भी लंबित है। एफएसएसएआई के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
- खाद्य व्यापार संचालकों और जनता की जागरूकता के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
- पंजीकरण विवाद के अधीन है, इस पर सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंजीयन प्राधिकारी होगा, हालांकि, यह अधिकार अन्य पदाधिकारियों के लिए भी प्रत्यायोजित किया जा सकता है
- ऑनलाइन लाइसेंस के लिए जिला स्तर पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं है
- एलो वेरा जूस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसका व्यवहार खाद्य उत्पाद के रूप में किया जाना चाहिए या आयुष उत्पाद के रूप में। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह खाद्य व्यापार संचालक के दावे पर निर्भर करेगा

24) राजस्थान

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया गया है
- 33 नामित अधिकारियों, 97 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और 7 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया गया है
- चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के 7 संयुक्त निदेशकों को, जोनल स्तर पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है
- 123 नए पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है
- राज्य में 7 प्रयोगशालाएं हैं और मोबाइल प्रयोगशाला की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है
- ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली प्रगति पर है
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया है

- कोई विशेष हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में संचालन के लिए राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता लाइन का उपयोग किया जा रहा है धन की जरूरत के आकलन की प्रक्रिया चल रही है

25) हरियाणा

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित कर दिया गया है
- 21 नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है
- जिले में 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार में अधिसूचित किया गया है
- राज्य में दो प्रयोगशालाओं है जिनके लिए अंतराल विश्लेषण किया गया है
- मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है
- ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण प्रणाली प्रक्रिया के अधीन है
- वेब साइट और हेल्पलाइन के विकास की प्रक्रिया चल रही है
- जागरूकता अभियान और कार्यशालाओं का कार्य प्रगति पर है
- 400 पदों को स्वास्थ्य विभाग से एफडीए में स्थानांतरित किया गया है
- राज्य में खाद्य प्रशासन को मजबूत करने के लिए 600 नए पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है
- लाइसेंस और पंजीकरण के क्षेत्र में नामित अधिकारियों, एओएस, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं
- आईईसी गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग से प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि लगभग एक तिहाई दूध महासंघों के पास कोल्ड चेन की सुविधा है, जो एफएसएस विनियमन, 2011 के अनुसार अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है, कोल्ड चेन की 100 प्रतिशत सुविधा बनाने के लिए काफी संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए, यह नया नियम लागू करना मुश्किल है। सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षा के लिए कोल्ड चेन की सुविधा निर्मित करना आवश्यक है किय इसलिए, इस आवश्यकता को हटाया नहीं जा सकता। हालांकि, खाद्य व्यापार संचालक विनियमन के त्वरित खंड को लागू करने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने खुदरा विक्रेताओं के पंजीकरण के बारे में पूछा कि क्या हर फुटकर विक्रेता को हर उत्पाद के लिए पंजीकृत किया जाना है। सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि मुख्य रूप से पंजीकरण/लाइसेंस परिसरों के लिए है और लाइसेंस में उत्पाद की श्रेणी का उल्लेख करना होगा।

उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि एफएसएसएआई को पानी के मानक विकसित करने पर जोर देना चाहिए और खाद्य उत्पादों की भारतीय मानक ब्यूरो समिति में एफएसएसएआई से एक प्रतिनिधि होने का सुझाव दिया। इसपर सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि केवल पेयजल, बोतल बंद पानी और एक घटक/संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी इस कानून के दायरे में है और एफएसएसएआई पानी के लिए मसौदा मानकों को विकसित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी कहा कि परामर्श कार्यशाला फरवरी, 2012 में आयोजित की जाएगी जिसमें मसौदा मानकों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो समिति में एफएसएसएआई के प्रतिनिधित्व के संबंध में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की गई है और सचेत निर्णय लिया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को स्वैच्छिक रूप में काम करने की वजह से एफएसएसएआई को भारतीय मानक ब्यूरो समिति में नहीं होना चाहिए।

डॉ एस पी वसीरेड्डी, विमता लैब्स ने सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के लिए रणनीतिक योजना साझा की। है। उन्होंने कहा, अधिकांश सार्वजनिक प्रयोगशालाएं बहु उत्पाद परीक्षण की एक भूमिका निभाते हैं और सार्वजनिक प्रयोगशालाओं को नए कानून के समर्थन में सक्रिय और कुशल बनाने में सक्षम करने के लिए एक बहु उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला की चुनौतियों की जांच किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

उन्होंने कहा कि इन बहु उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की चुनौतियों पर काबू पाने के कुछ संभव समाधान हैं यानी भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का विश्लेषण और प्रत्येक प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण किए जाने वाले उत्पादों की न्यूनतम संख्या पर पहुंचना। इसलिए उत्पाद/श्रेणी के अनुसार प्रयोगशालाओं को विकसित करने और बढ़ने की जरूरत है:

- पेय
- मसाला और छौंक
- मिठाई और कन्फेक्शनरी
- चटपटे / नमकीन
- बेकरी उत्पाद
- चाय, कॉफी, कोको, कासनी व आसव
- दूध
- मक्खन, घी, आइसक्रीम और अन्य दूध उत्पाद
- खाद्य तेल, वसा और वनस्पति
- अनाज और दलहन
- फल और सब्जी उत्पाद

– बच्चों के खाद्य पदार्थ

कार्यसूची मद सं. 7: राष्ट्रीय दूध सर्वेक्षण

"दूध में मिलावट पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण" पर चर्चाएँ आयोजित की गई। दूध की गुणवत्ता का पता लगाने और देश भर में दूध में मिलावट के विभिन्न प्रकारों की पहचान करने के लिए निगरानी (स्नैप शॉट सर्वेक्षण) के एक भाग के रूप में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, और कोलकाता में स्थित एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया था।

प्राप्त परिणामों को संकलित और उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, और इसका इरादा किसी भी राज्य या निर्माता को लक्षित करना नहीं है। पूर्वी क्षेत्र से यानी (बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 250 नमूने) लिए गए 14 प्रतिशत नमूने विश्लेषण में डिटर्जेंट के चिह्नों की उपस्थिति की वजह से गैर–अनुरूप पाए गए। इसका कारण दूध की देखभाल में स्वच्छता और साफ–सफाई की कमी हो सकती है। सर्वेक्षण में कोई सिंथेटिक दूध नहीं पाया गया था। सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में नमूनों को एसएनएफ के प्रतिशत और वसा के मेल न होने की वजह से "गैर अनुरूप" पाया गया, जिससे दूध की गुणवत्ता कम पाई गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ उचित सावधानियों के साथ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित होना हो। इसी प्रकार उन नमूनों का मामला है जिन्हें दूध (ताजा दूध माना जा रहा है) कहा जाता है लेकिन इनमें स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) मिला पाया गया। अगर इनमें मिलाया जाने वाला पानी संदूषित हो तो दूध के ये प्रकार के स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं।

पशुपालन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि एसएमपी मिलाने का गैर–अनुरूपता के रूप में उल्लेख नहीं किया जा सकता 'फ्लश सीजन' के दौरान दूध के अधिक उत्पादन की वजह से दूध पाउडर को संसाधित किया जाता है, और मांगों को पूरा करने के लिए लीन मौसम के दौरान उसे पुनर्गठित किया जाएगा।

उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि ने तमिलनाडु में किए गए दूध पर एक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में उल्लेख किया, जिसके निष्कर्षों से पता चलता है कि एसएमपी को मुख्य रूप से ठोस गैर वसा की मात्रा को बढ़ाने और दूध की कीमत में वृद्धि करने के लिए जोड़ा जाता है।

सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर, 68.4 प्रतिशत नमूनों को एफएसएस विनियम के अनुरूप नहीं पाया गया। इस संदर्भ में, यह "गैर–अनुरूपता" और "असुरक्षित खाद्य" के

बीच के अंतर को बताना महत्वपूर्ण है। नियमों के तहत, 10 प्रकार के दूध यानी, भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी या भेड़ का दूध, मिश्रित दूध, मानकीकृत दूध, पुनर्निर्मित दूध, टोन्ड दूध, डबल टोन्ड दूध, फुल क्रीम दूध, स्किम्ड दूध के लिए मानक निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें से दूध की पहले चार श्रेणियां परिभाषा से 'उसमें कुछ जोड़े या निकाले बिना स्वस्थ दुधारू पशु के पूरा दूध देने से व्युत्पन्न सामान्य स्तन स्राव' दूध हैं और इनका निर्धारित मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। अन्य श्रेणियों के दूध के लिए, विनियम या वसा/एसएमपी को हटाने के द्वारा एसएनएफ और वसा की मात्रा के मानकीकरण की अनुमति देते हैं।

पहले चार वर्ग के लिए दूध यानी भैंस के दूध यानी गाय का दूध, बकरी या भेड़ के दूध को लीन /फ्लश सीजन की परवाह किए बिना ताजा दूध होना चाहिए, इसमें एसएमपी के साथ फिर से निर्मित करने की अनुमति नहीं है। यदि फिर से निर्मित किया जाता है तो एक उचित दावा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जनता को जागरूक बनाने के लिए कि वे फिर से निर्मित दूध का उपभोग कर रहे हैं लेबल में एसएमपी के मिलाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मानकीकृत दूध, फिर से निर्मित दूध, टोन्ड दूध, डबल टोन्ड दूध, स्किम्ड दूध और फुल क्रीम दूध के मामले में, एक हद तक एसएमपी की अनुमति दी गई है, लेकिन लेबल में एक स्पष्ट दावा किया जाना चाहिए।

दूध का प्रबल उत्पादन असंगठित क्षेत्रों के हाथों में निहित है। इस तरह के सर्वेक्षण जनता में अच्छी जागरूकता उत्पन्न करते हैं। दूध का सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण भी अस्तित्व में आ जाएगा। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एफएसएस अधिनियम, 2006 में किए गए प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि दूध में मिलावट को रोका जा सके।

<u>कार्यसूची मद सं 8</u>: एनआईएसजी द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की स्थिति पर प्रस्तुति

एनआईएसजी द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की स्थिति पर प्रस्तुति पेश की गई थी। प्रस्तुति में खाद्य व्यापार संचालकों के लिए एक एकीकृत, केंद्रीकृत, सुरक्षित, मापन योग्य कम्प्यूटरीकृत लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य, एनआईएसजी को सौंपा एनआईएसजी को सौंपे गए कार्य, पूरे हो चुके कार्य, चल रहे कार्यों और भविष्य कार्य, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) की प्रक्रिया सहित लाइसेंस और पंजीकरण के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि यह एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल केंद्रीकृत प्रणाली है जो एनआईसी डाटा सेंटर पर होस्ट है और प्रत्येक राज्य द्वारा अपने निजी सॉफ्टवेयर की स्थापना का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सेंट्रल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन श्री वी.एन. गौड़(सीईओ, एफएसएसएआई) द्वारा 28 दिसंबर, 2011 शुरू की गई थी। क्रमशः 12.01.2012 और 13.01.2012 को

महाराष्ट्र और गुजरात में भी एफएलआरएस शुरू किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली, गोवा और आंध्र प्रदेश ने स्वेच्छा से खाद्य व्यापार संचालक लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली का प्रायोगिक कार्यान्वयन किया है। उन्होंने, किए प्रयासों के आंकलन अर्थात परामर्श, परियोजना प्रबंधन, सॉफ्टवेयर के अनुकूलन, सहायता डेस्क/राज्य स्तर सहायता, जिला स्तर पर समर्थन और प्रशिक्षण, संसाधनों की संख्या, महीनों की अवधि, अनुमानित कार्य महीनों और अनुमानित लागत के मामले में प्रबंधन/क्षमता निर्माण में परिवर्तन के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने, यह भी कहा कि राज्यों को एफबीओ–एफएलआरएस आरंभ करने के लिए अपनी तैयारी और प्रायोगिक तौर पर एक या दो जिलों की पहचान करने और राज्य के बाकी हिस्सों के लिए एक चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन की योजना और समय प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित राज्यों की जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त क्षेत्र के लिए राज्य और एनआईएसजी के साथ अलग से समझौते किया जा सकते हैं।

<u>कार्यसूची मद सं 9:</u> हवाई अड्डों और छावनियों पर परिचालन के लिए खाद्य व्यापार संचालकों की लाइसेंसिंग

हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर खाद्य व्यापार संचालकों को संभालने के लिए एफएसएसएआई की क्षमता पर्याप्त नहीं है इसलिए सीईओ ने उक्त कार्यसूची पर सुझाव आमंत्रित नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र ने कहा कि पीएफए के तहत, एनएचआरएम ने हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर परिचालन करनें वाले खाद्य व्यापार संचालकों के लिए लाइसेंस जारी किए है।

सीईओ ने सुझाव दिया कि चार मेट्रो शहरों– दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मामले में सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए नामित अधिकारी विमानपत्तन/बंदरगाहों पर सभी खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस जारी कर सकते हैं। हालांकि देश के अन्य हवाई अड्डों के मामले में, एफएसएसएआई लाइसेंस जारी करने और नियमित रूप से निरीक्षण का संचालन करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत कर सकता है।

सीएसी की छठी बैठक से कार्रवाई बिंदु: बैठक के दौरान आयोजित की गई चर्चा के आधार पर कार्यान्वयन के निम्नलिखित बिंदु उभरे।

- सीईओ, एफएसएसएआई ने विवेचना उपयोगी बनाने के लिए और उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए सीएसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया
- विभिन्न राज्यों में मानव शक्ति की कमी पर पहले से ध्यान दिए जाना चाहिए, इसलिए राज्य सरकारों को पदों की सीधे मंजूरी से अधिक बल बनाने के प्रयास करने चाहिए,
- अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में स्थानीय

निकाय को शामिल करना चाहिए। उम्मीद है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में, केवल केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा

- राज्य में खाद्य सुरक्षा पेशेवरों का एक कैडर विकसित करना आवश्यक है, जो प्रतिनियुक्ति पर स्थानीय निकायों में काम कर सकते हैं और इन्हें राज्य में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्व के साथ आम कैडर से संबंधित होना चाहिए, निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- जनता के बड़े समूह और दुर्गम क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल प्रयोगशाला सुविधाओं को भी महत्व दिया गया और विनिर्देशों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक राज्य में एक मोबाइल प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है इसलिए एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में आम डिजाइन और क्यूआर रखा जाएगा।
- खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना समय की मांग है। सड़क खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ क्योंकि आबादी के अधिकांश लोग उसी पर निर्भर करते हैं, विभिन्न हितधारकों अर्थात् उपभोक्ताओं, खाद्य व्यापार संचालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम पर जोर दिया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सप्ताह में ईओआई जारी किया जाएगा। राज्य एजेंसियों का चयन कर सकते हैं और लागत को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- सरकार की हर 4–5 जिलों के बुनियादी परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त मानकों के प्रयोगशालाओं का समूह स्थापित करने और कीटनाशक/भारी धातुओं आदि जैसे सभी मापदंडों के परीक्षण के लिए जोनल खाद्य प्रयोगशालाएं (हर 10 जिलों के लिए) स्थापित करने की योजना है।
- राज्यों के पास क्षमता निर्माण के लिए उनकी अपनी संस्थाएं होनी चाहिए (प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को बाहर भेजने की बजाय)
- स्थानीय स्तर पर खाद्य व्यापार संचालकों के लिए लाइसेंस/पंजीकरण पर वीडियो प्रदर्शन की योजना भी बनाई जा सकती है
- प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता क्षेत्रीय आधार पर उत्पाद विशिष्ट हो सकती है, मसालों का परीक्षण उनके लिए समर्पित प्रयोगशालाओं में किया जा सकता है, इसी प्रकार फलों का परीक्षण फल के साथ संबंधित प्रयोगशालाओं किया जा सकता है। इस तरह के प्रयासों से वजन और विश्वास हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षण करने के लिए क्षमता निर्माण होगा
- राज्य को ऑनलाइन लाइसेंस के बारे में, इस तरीके से आंतरिक मानकों की पहचान करनी होगी जिससे एक साझा मंच और सॉफ्टवेयर, प्रारूप बनाए रखा जा सके।
- लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्षेत्रीय भाषाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए होना चाहिए हालांकि ध्यान

मिलावट विरोधी अभियानों से नहीं हटना चाहिए विशेष रूप से उत्सव के मौसम, गर्मी के मौसम और मानसून के दौरान

- विभाग को मिलावट के लिए संवेदनशील क्षेत्रों से अधिक नमूने एकत्र करने के लिए सक्रिय होना चाहिए।
- शिशु आहार और स्कूलों में तथा उनके आसपास परोसे जाने वाले भोजन जैसे असुरक्षित वर्ग के उत्पादों से नमूने एकत्र किए जा सकते हैं
- न्यायनिर्णयन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी से शुरू किया जाएगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामित अधिकारी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं

सीएसी ने सीएसी के अध्यक्ष के रूप में श्री वी.एन. गौड़ द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार किया और सत्र की अध्यक्षता करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

.....

अनुलग्नक–1

दिनांक 18 जनवरी 2012 को शांगरी–ला'ज–इरोज होटल, 19 अशोक रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में 11.00 बजे आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की छठी बैठक के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे।

1. श्री वी. एन. गौड़, अध्यक्ष, सीएसी एवं सीईओ, एफएसएसएआई
2. श्री आर. एफ. लोथा, अतिरिक्त आयुक्त एफडीए, स्वास्थ्य एवं परिवार निदेशालय कल्याण, नागालैंड।
3. श्री एस. एन. संगमा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, मेघालय।
4. श्री यू. के. मित्रा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, अरुणाचल प्रदेश
5. श्री राजेंद्र सिंह पाल, नामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय, उत्तराखंड
6. श्री सी. आर. राणा (आईएएस), आयुक्त एफडीए, हरियाणा
7. डॉ एस एस तोमर, खाद्य विश्लेषक, एफडीए, छत्तीसगढ़
8. श्री अशोक खुल्लर, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), एफडीए, हरियाणा
9. डॉ एस जी बिस्वाल, निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य सह आयुक्त खाद्य सुरक्षा, ओडिशा
10. डॉ पी.के. वत्स, नामित अधिकारी, पीएफए विभाग, दिल्ली सरकार
11. डॉ एच.जी. कोशिया, आयुक्त, एफडीसीए, गुजरात
12. डॉ ए. रितिंद्र मोहन सिंह, राज्य महामारी विशेषज्ञ, स्वास्थ्य निदेशालय, मणिपुर
13. श्री बी. सी. जोशी, उपायुक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली
14. श्री. अजीत बी. चौहान, उप सचिव, वाणिज्य विभाग
15. डॉ एस. पी. बसीरेड्डी, विमता लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद
16. श्री संजाओबा, राज्य के खाद्य विश्लेषक, स्वास्थ्य विभाग, मणिपुर
17. सुश्री सी.वी. सरोदा, अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
18. श्री ए.के. ओझा, सहायक निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
19. श्री टी. एन. रमनाजियन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु
20. बी. प्रशांत कुमार, निदेशक, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन और विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के विभाग
21. श्री सलीम ए. वेलजी, निदेशक, खाद्य और औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, गोवा
22. श्री लाइ सवमा, खाद्य सुरक्षा उप–आयुक्त, आइजोल, मिजोरम
23. श्री आर.के. आहूजा, नामित अधिकारी, पीएफए विभाग, भारत सरकार, दिल्ली
24. डॉ सतबीर सिंह, एसएमओ सह नामित अधिकारी, चंडीगढ़
25. डॉ ए गणेशन, संयुक्त निदेशक (पीएफए), तमिलनाडु
26. श्री आर. देसीकन, ट्रस्टी, कन्सर्ट, चेन्नई

27. श्री रोहित जामवाल, संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
28. डॉ जी. एल. उपाध्याय, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, पुडुचेरी
29. डॉ श्रुति राय भारद्वाज, उप निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
30. श्री बी.एस. रामप्रसाद, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, कर्नाटक
31. डॉ श्रीनिवास, संयुक्त निदेशक, खाद्य सुरक्षा, कर्नाटक
32. सुश्री अर्चना अग्रवाल, सचिव एवं आयुक्त, एफडीए, उत्तर प्रदेश
33. डॉ एस सी खुराना, कृषि एवं सहकारिता के विपणन एवं निरीक्षण विभाग का निदेशालय, कृषि मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद विपणन एवं निरीक्षण विभाग के निदेशालय
34. डॉ जे पी सिंह, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, चंडीगढ़
35. डॉ आर.के. गुप्ता, उप निदेशक (खाद्य), चंडीगढ़
36. श्री रूपेंद्र चौधरी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, पश्चिम बंगाल
37. श्री संजय कुमार सक्सेना, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, दिल्ली
38. श्री महेश जगड़े, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, महाराष्ट्र
39. डॉ अनिल शर्मा, सलाहकार एफएसएसएआई, देहरादून, उत्तराखंड
40. श्री संजय कुमार, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, बिहार
41. श्री सतीश गुप्ता, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर
42. श्री संजीव कुमार, सहायक नियंत्रक, खाद्य, जम्मू और कश्मीर
43. डॉ जे पी धमीजा, अतिरिक्त निदेशक (आरएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर, राजस्थान
44. श्री अश्विनी कुमार राय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश
45. श्री जी,एच. राठौड़, संयुक्त आयुक्त (एफडीए), महाराष्ट्र
46. श्री सुकुमार, उप सचिव (विपणन), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
47. श्री कुलदीप सिंह ठाकुर, उप आवासीय आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, नई दिल्ली

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।